वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकडा, सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछने गए तरीके के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती । तथापि, सितम्बर, 1994 (भारतीय रिजर्व बैंक के पास अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के श्रेणी-वार अतिदेय अग्रिमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है;

श्रेणी	अतिदेव अग्रिम
बड़े और मझौले उद्योग	8153.12 करोड़ रूपए
लघु उद्योग	5419.85 करोड़ रूपए

वार्षिक मुद्रास्फीति दर का ईष्टम स्तर

1493. **श्री रामजेठमलानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूरे विश्व में मुद्रास्फीति का ईष्टम स्तर 3 प्रतिशत स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि विश्व के सभी विकसित और विकासशील देशों ने अपने वार्षिक मुद्रास्फीति को इस स्तर तक लाने के प्रयास किए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन, मलेशिया, अर्जेंटीना, ताइबान आदि देशों की वार्षिक मुद्रास्फीति दर क्या है, और

(ड) सरकार द्वारा भारत में मुद्रास्फिती की दर को इस स्तर लाने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) 2.5 से लेकर 3 प्रतिशत की कम मुद्रास्फीति दर कुल मिलाकर विकसित देशो की विशेषता रही है जैसाकि कुछ चुनिन्दा विकसित देशों में तीन समय अवधियों 1985-89, 1990-92 और 1993-96 के लिए नीचे दर्शाया गया है।

औसत वार्षिक मुद्रास्फीति दरें (प्रतिशत)

	यू.के.	स्वीडन	कनाडा	स्पेन	आस्ट्रेलिया	न्यूजीलैंड	जी-7	भारत
1985-89	5.3	5.6	4.3	6.9	7.8	11.3	3.4	6.5
1990-92	6.4	7.4	4.0	6.2	3.8	3.3	4.1	12.0
1993-96	2.5	2.7	1.4	4.4	2.7	2.3	2.4	8.9

कुछ देशों ने हाल ही में अपनी-अपनी मौट्रिक नीतियों में मुद्रा-स्फीति के लक्ष्य-निर्धारण का ढांचा बनाने का प्रयास किया है। भारत में मुद्रा विस्तार को विवेकपूर्ण सीमाओं में रखना, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखते हेतु भा.रि. बैंक द्वारा अपनाया गया एक महत्वपूर्ण सम्बन्धी तारापोर समिति ने हाल ही में 3 से 5 प्रतिशत की मुद्रास्फीति की लक्षित दर बनाए रखने का प्रस्ताव किया है।

(ड) सरकार ने मुद्रास्फीति दर के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है न ही उसे प्राप्त करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है।

Monitoring of Rating Agencies by Government

1494. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) that in the light of the recent CRB Scam whether such rating systems of ICRA, CRISIL, etc. are based on critical examination of expected costs and returns of various under-lying projects vis-a-vis corresponding financial instruments/ shares/bonds for financing such project; and